JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

शीर्षकः– सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना की प्रभावशीलता का

मूल्यांकनः

(A Critical Evaluation of the "Har Ghar Nal Ka Jal" Scheme under Saat Nischay Yojana)

उत्तम कुमार (शोधार्थी) स्नातकोत्तर ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारी प्रबंधन विभाग, तिलकामॉझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार

डा0 प्रभा कुमारी, प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग,तिलकामॉझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार

सरांश (Abstract) :

यह शोध पत्र बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सात निश्चय योजना के अन्तर्गत सात योजनाओं में से एक योजना "हर घर नल का जल" योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना हैं। योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को स्वच्छ साफ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। यह अध्ययन योजना की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और प्रशासनिक पक्षों का विश्लेषण करता है और इसके निष्पादन में आई चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द (Key Word): हर घर नल का जल, जल जनित रोग, महिला सशक्तिकरण, जल आपूर्ति, जल संचरण, स्वास्थ्य सुधार।

प्रस्तावना (Introduction):

बिहार, भारत के सबसे पिछडे राज्यों में एक माना जाता है जहॉ बुनियादी सुविधाओं की कमी लम्बें समय से बिहार के विकास में बाधक रही है। वर्ष 2015 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सात निश्चिय योजना की शुरआत की गई जिससे बिहार के विकास में नये आयाम का उदय हुआ एवं इसके अन्तर्गत बिहार के सात प्रमुख क्षेत्रों जैसे– शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, सडक, बिजली, पानी(जल), और महिला सशिक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। इस योजना का सबसे व्यावहारिक एवं प्रत्यक्ष लाभ देने वाला भाग रहा हर घर नल का जल योजना। इस योजना के अन्तर्गत सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामिण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी घरों को पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ व साफ पेयजल उपलब्ध कराना है।

योजना की रूपरेखा (Scheme Overview):

हर घर नल का जल योजना का लक्ष्य था कि वर्ष 2020 तक हर घर में नल द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। योजना को दो प्रमुख विभागों– पंचायती राज विभाग (ग्रामीन क्षेत्र) और नगर विकास एवं आवास विभाग (शहरी क्षेत्र) द्वारा क्रियान्वित किया गया।

मुख्य विशेषताएँ :

1. प्रत्येक घर को व्यक्तिगत नल कनेक्शन
2. जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना

3. पाइप लाइन, पानी टंकी और मोटर पम्प की व्यवस्था
4. जल गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था
5. महिलाओं को जल समितियों में शामिल कर सहभागिता सुनिश्चित करना

योजना की सामाजिक प्रभावशीलता (Social Impact):

1. महिला सशक्तिकरण–

इस योजना ने महिलाओं के जीवन में बडा बदलाव लाया है। महिलाओं को पानी लाने में लगने वाले समय की वचत से महिलाओं एवं बालिकाओं शिक्षा, आय सृजन और बच्चों की देखभाल में समय दे पा रही है जिससे बालक बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार हुआ हैं।

2. स्वास्थ्य सुधार–

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है, खासकर बच्चों में डायरिय, हैजा और टाइॅाइड जैसी बिमारियों में कमी आई है।

3. समाजिक समरसता–

जल स्त्रोत को लेकर होने वाले विवादों में कमी आई है। अब हर घर में नल का जल मिलने से सामाजिक तनाव कम हुआ है और आपसी सहयोग की भावना बढी है।

आर्थिक प्रभावशीलता (Economic Impact):

1. स्वास्थ्य व्यय में कमी–

जलजनित रोगों में कमी आने से लोगों का स्वास्थ्य एवं उपचार पर होने वाले व्यय में कमी आई है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

2. उत्पादकता में वृद्धि–

स्वच्छ जल की उपलब्धता से श्रमिकों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। जल की उपलब्धता से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कार्यो को स्थायित्व मिला है।

3. स्थानीय रोजगार–

योजना के कियान्वयन में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हुआ– जैसे निर्माण, पाइपलाइन बिछाना, मरम्मत आदि कार्यो में लोगों को काम मिला।

तकनीकी और प्रशासनिक मूल्यांकन (Technical & Administrative Assessment):

1. पाइपलाइन और उपकरणों की गुणवत्ता–

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कई इलाके में निम्न स्तर के पाइपलाइन का उपयोग किया गया है, जिससे पानी की लीकेज, क्षति और जल आपूर्ति बाधित हो रही है।

2. जल गुणवत्ता परीक्षण की कमी–

जल में आयरन, आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसे खतरनाक तत्वों की उपस्थिति कई स्थानों में पाई गई, लेकिन समय पर परीक्षण एवं निवारण की व्यवस्था नहीं हो रही है।

3. विद्युत निर्भरता –

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जल की आपूर्ति मुख्यतः मोटर पम्प के द्वारा किया जाता है, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण जल वितरण की आपूर्ति पूर्णरूप से बाधित हो जाती है।

जनसहभागिता और समुदाय आधारित निगरानी (Community Participation):

ग्राम जल समितियाँ–

कुछ ग्राम पंचायतों और वार्ड स्तर पर महिला नेतृत्व में जल समितियाँ बनी है जिन्होंने जल वितरण की निगरानी लगातार कर रही है जिससे पारदर्शिता और ग्रामीनों सहभागिता बढी है।

चुनौतियाँ (Challenges):

1. निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार और ठेकेदारी व्यवस्था की अनियमितता
2. तकनीकी कर्मचारियों की कमी
3. ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता की कमी

केश अध्ययन (Case Studies):

बिहार राज्य के भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगाँव प्रखण्ड के सभी पंचायतों में हर घर नल का जल योजना संचालन किया जा रहा है जिसमें कुछ वार्ड के घरों में पानी वितरण किया जा रहा है परन्तु वार्ड में जल वितरण की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल आपूर्ति बाधित है। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति से जुडी किसी भी समस्या को लेकर ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था की गई, जिसका टोल– फ्री नम्बर 18001231121 / 18003451121 एवं WhatsApp नम्बर 8544429024 / 8544429082 है।

सुझाव (Suggestions):

1. जल गुणवत्ता परीक्षण को मासिक/त्रिमासिक और नियमित किया जाए।
2. स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय।
3. वर्षा जल संचयन को योजना में समाहित किया जाए।
4. जनसहभागिता बढाने के लिए जल संरक्षण अभियान चलाए जॉए।
5. जनसुनवाई तंत्र को और वेहतर बनाया जाए।
6. ऑनलाइन शिकायत के समस्या समाधान के उपरांत इसका शिकायत कर्त्ता का प्रतिक्रिया लिया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion):

हर घर नल का जल योजना बिहार मे ंदक क्रांतिकारी पहल रही है जिससे लाखों लोंगों को स्वच्छ जल की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह योजना सामाजिक समावेशिता, स्वास्थ्य सुधार और महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुई है। हालाँकि, योजना में तकनीकी और प्रशासनिक कमियाँ है जिन्हें दुर किए बिना इसकी दीर्घकालिन सफलता असंभव है। पारदर्शिता, निगरानी, रखरखाव और सामुदायिक सहभागिता को केन्द्र में रखते हुए योजना का पुनर्गठन आवश्यक है। यदि सुधारात्मक कदम उठाए जाँए, तो यह योजना न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकती है।

सन्दर्भ सूची (References):

1. बिहार सरकार, पंचायती राज विभाग के सात निश्चय योजना का कार्यान्वयन रिपोर्ट (2016–2023)।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के हर घर नल का जल रिपोर्ट एवं मूल्यांकन (2020)।
3. नीति आयोग(2019) – भारत में जल संकट और समाधान की दिशा में प्रयास।
4- यूनिसेफ रिपोर्ट 2021– Safe Water Supply and Sanitation in Bihar: An Impact Study।
5- Indian Express 2022- Bihar's Har Ghar Nal Ka Jal scheme gets mixed response".
6. एम. सिंह, 2021– ग्राम विकास और जल योजनाएँः एक तुलनात्मक अध्ययन भारतीय सामाजिक समीक्षा, खण्ड 47.
7. सेंटर फॉर वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेस टाटा इंस्टिटसूट
8. Center for water policy and government(CWPG), Tata Institute for social sciences (TISS), Community Engagement in Water Access: Lessons from Bihar।